PRGI No. UPHIN/25/A1697

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 033
दि. 02.06.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

भारत की आधिकारिक यात्रा पर म्यांमार के राष्ट्रपति , एनएसए डोभाल और जयशंकर के बाद पीएम मोदी से हुई मुलाकात

(जीएनएस)।

नई दिल्ली : भारत और म्यांमार ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के साथ ही व्यापार, निवेश, संपर्क (कनेक्टिविटी), विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। सोमवार को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुई विस्तृत वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की।

म्यांमार की हर मदद को तैयार भारत

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार में शांति और संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भारत हर तरह की मदद को तैयार है। उन्होंने संघीय शासन व्यवस्था और आर्थिक विकास के अनुभव साझा करने की भी बात कही। विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति की बातचीत व्यापक रही और दोनों देशों ने शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।

उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के लिए एक भरोसेमंद पड़ोसी और संकट के समय में पहला सहयोगी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत की ह्लनेबरहुड फर्स्टह्न, ह्लएक्ट ईस्टह्न

और ह्लमहासागरह्न नीतियों के अनुरूप भारत हमेशा म्यांमार का सहयोग करता रहेगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे राष्ट्रपति यू मिन

राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग का सोमवार को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात का कार्यक्रम है। वे राजधानी में ह्लद लाइट एंड द लोटसः रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वनह्न नामक सांस्कृतिक प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे।

आपको बता दें कि यह म्यांमार राष्ट्रपति की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। उनके साथ कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधियों का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वे मुंबई में व्यापारिक बैठकों और विभिन्न स्थलों का भी दौरा करेंगे। इससे पहले रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की थी, जबकि 30 मई को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी उनसे बातचीत की थी और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की बात कही थी।

पीएम स्वनिधि योजना के छह साल पूरे, 75 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को मिला आर्थिक लाभ

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के छह वर्ष पूरे होने पर इसकी उपलब्धियों की सराहना की। योजना के तहत 75 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को 17,800 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण देकर वित्तीय समावेशन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के छह वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसकी उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना ने लाखों रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को बिना गारंटी ऋण, वित्तीय समावेशन और आर्थिक उन्नति के नए अवसर प्रदान किए हैं। उन्होंने इसे विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

कोविड-19 महामारी के दौरान जून 2020 में शुरू की गई इस योजना को केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक बढ़ा दिया है। इसके लिए 7,332 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ बजटीय प्रावधान किया गया है तथा ऋण सीमा में भी वृद्धि की गई है। सरकार का लक्ष्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच बनाना और यूपीआई-आधारित क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं के माध्यम से स्वरोजगार को और अधिक प्रोत्साहित करना है।

योजना से कई रेहड़ी-पटरा वालों के लाभ

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना ने असंख्य रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, गरिमा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का माध्यम भी है। प्रधानमंत्री ने सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका परिश्रम और उद्यमशीलता देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रही है।

केंद्र सरकार के अनुसार, पीएम स्वनिधि योजना ने लाखों छोटे व्यापारियों के जीवन में आत्मविश्वास, अवसर और बेहतर भविष्य की संभावनाएं पैदा की हैं। सरकार ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया,

जिसने आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत किया है।

लगभग 800 करोड़ रुपये दिए गए

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत ब्याज सब्सिडी और कैशबैक प्रोत्साहनों के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इससे डिजिटल भुगतान और समय पर ऋण चुकाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है तथा लाभार्थियों में बेहतर वित्तीय अनुशासन विकसित हुआ है।

अब तक 75 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को 112 लाख से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 17,800 करोड़ रुपये से अधिक है। इन ऋणों ने छोटे कारोबारियों को अपने व्यवसाय को पुनः शुरू करने, आवश्यक सामान की खरीद करने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने में सहायता की है।

95 प्रतिशत लाभार्थी पहली बार लोग ले पाए

योजना के तहत लगभग 95 प्रतिशत लाभार्थियों ने पहली बार औपचारिक संस्थागत ऋण प्रणाली तक पहुंच बनाई, जबकि 30 प्रतिशत लाभार्थियों ने पीएम स्वनिधि ऋण से आगे बढ़कर अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्राप्त की। सरकार के अनुसार, इस योजना के कारण लाभार्थियों की वार्षिक आय में औसतन लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

सरकार ने बताया कि रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं ने अब तक 841 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन किए हैं, जिनका कुल मूल्य लगभग 9 लाख करोड़ रुपये है। इससे वे तेजी से विकसित हो रही डिजिटल अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा लगभग 6 लाख स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का प्रशिक्षण दिया गया है। योजना के लगभग 53 लाख लाभार्थी, जिनमें 70 प्रतिशत वंचित और कमजोर वर्गों से आते हैं, वित्तीय समावेशन और आर्थिक अवसरों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

लगभग 46 प्रतिशत महिलाओं को मिला लाभ

सरकार के अनुसार, योजना के लाभार्थियों में लगभग 46 प्रतिशत महिलाएं हैं, जिन्हें बेहतर आर्थिक स्थिरता, आत्मविश्वास और आजीविका के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। इससे उनके दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है तथा आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है।

'छात्र अब घरों में झाड़ू पोंछा लगाने लगे', परीक्षाओं में छात्राओं के शानदार नतीजों पर सीएम योगी ने ली चुटकी

(जीएनएस)।

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की बोर्ड परीक्षाओं में छात्राओं के मुकाबले छात्रों का रिजल्ट कमजोर होने पर छात्रों की चुटकी ले ली। उन्होंने कहा कि लगता है कि छात्र अब घरों में झाड़ू पोंछा लगाने लगे हैं। लगता है कि कुछ छात्र मोहल्ले में भी झाड़ू लगाने लगे हैं, तभी तो परीक्षाओं में छात्राओं की तुलना में उनके अंक कम आ रहे हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यह बात लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा विभाग की केंद्र एवं राज्यस्तरीय बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों व प्रधानाचार्यों के सम्मान समारोह में कही।

मां-बाप छात्रों से ज्यादा काम ले रहे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, 'हम लोग ये मानते थे कि छात्राएं घर में अपनी माताओं के काम में भी सहयोग करती हैं। लगता है कि अब परिवर्तन आ गया है। छात्र घर में झाड़ू

पोंछा ज्यादा लगाने लग गए हैं। या लगता है कि मां-बाप उनसे ज्यादा काम ले रहे हैं। सब्जी लेने के लिए भेजते होंगे। हो सकता है घर और मोहल्ले में भी कुछ झाड़ू लगा रहे होंगे। इसीलिए छात्रों के अंक इतने कम है और छात्राएं मेहनत कर रही हैं और मेरिट में उन्होंने अच्छा स्थान प्राप्त किया है।'

छात्राओं से प्रेरणा लें छात्र

उन्होंने कहा कि, 'यह एक सुखद लक्षण है। लेकिन छात्रों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि छात्राएं घर में परिवार का सहयोग करते हुए भी अच्छे अंक प्राप्त कर रही हैं, मेरिट में ज्यादा स्थान प्राप्त कर रही हैं, तो छात्र कम से कम उनका ही अनुसरण कर लें।'

बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, 'मेरा मानना है कि बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और देश और समाज को भी आगे बढ़ाएगी। हम सबके सामने यह इस रिजल्ट के माध्यम से एक संदेश बहुत स्पष्ट आ गया है।'

'8 लाख हस्ताक्षर, 1 करोड़ प्रभावित', CJP प्रमुख ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन का किया ऐलान

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार पर देश की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताओं का

आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। दीपके का दावा है कि नीट, सीबीएसई, एसएससी और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों से एक करोड़ से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं, जबकि उनकी ऑनलाइन याचिका को अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल चुका है।

नीट यूजी 2026: 21 जून को ऑनलाइन या CBT मोड़ में होगा री-एग्जाम? सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया साफ

(जीएनएस)।

नीट यूजी 2026 को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट और संसद दोनों स्तर पर परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक ओर लाखों छात्र 21 जून को होने वाली री-नीट परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर परीक्षा के तरीके और सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है। पेपर लीक के आरोपों के बाद कई छात्र, शिक्षा विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधि मांग कर रहे हैं कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा को अब पारंपरिक पेन-एंड-पेपर मोड के बजाय कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) में कराया जाए।

इसी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। हालांकि अदालत ने फिलहाल परीक्षा का फॉर्मेट बदलने से इनकार कर दिया है। वहीं संसद की एक महत्वपूर्ण समिति ने भी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली और परीक्षा प्रबंधन को लेकर जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि ठएएळ वक्र को सुरक्षित बनाने के लिए इसे कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदला जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि 21 जून को प्रस्तावित री-टेस्ट भी ऑनलाइन मोड में कराया जाए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इसी तरह की याचिकाओं पर पहले भी फैसला दिया जा चुका है। कोर्ट ने फिलहाल किसी तरह का निर्देश देने से इनकार करते हुए मामले को लंबित रखने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि अवकाश के बाद अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ इस मामले पर भी सुनवाई की जाएगी।

जस्टिस नरसिम्हा ने क्या कहा

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से फिर यह दलील दी गई कि ऑनलाइन परीक्षा पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने का बेहतर तरीका हो सकता है। इस पर जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि इस समय परीक्षा के तरीके में बदलाव का सवाल नहीं उठता। उन्होंने कहा कि पहले ही पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी और अब दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है। ऐसे में फिलहाल किसी नए निर्देश की जरूरत नहीं है।

याचिका में राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी की गई। इसमें सुझाव दिया गया था कि प्रश्नपत्रों को डिजिटल और एन्क्रिप्टेड लिंक के जरिए परीक्षा केंद्रों तक भेजा जाए। परीक्षा शुरू होने से केवल 30 से 60 मिनट पहले स्थानीय स्तर पर प्रश्नपत्र प्रिंट किए जाएं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे परिवहन और भंडारण के दौरान पेपर लीक का खतरा काफी कम हो सकता है।

21 जून को ऑफलाइन ही होगी री-नीट परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद अब लगभग साफ हो गया है कि 21 जून को होने वाली ठएएळ वक्र 2026 री-परीक्षा पुराने पेन-एंड-पेपर फॉर्मेट में ही आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अब तक मेडिकल प्रवेश परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड में ही करती रही है।

पेपर लीक के बाद बढ़ी ऑनलाइन परीक्षा की मांग

2024 में सामने आए पेपर लीक विवाद के बाद कई विशेषज्ञों ने सुझाव दिया था कि ठएएळ को ऑनलाइन और कई चरणों में आयोजित किया जाए। हालांकि इन सुझावों को अब तक लागू नहीं किया गया। इस बीच छात्रों का एक वर्ग लगातार मांग कर रहा है कि कम से कम री-परीक्षा को ऑनलाइन कराया जाए ताकि किसी नई गड़बड़ी की आशंका न रहे।

हस्ताक्षर विवाद में मचा बवाल, बागी विधायकों और टीएमसी में छिड़ी जंग, दो मोर्चों पर घिरी ममता बनर्जी की पार्टी

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दो विधायकों के निष्कासन के बाद अंदरूनी घमासान तेज हो गया है। निष्कासित विधायक संदीपान साहा ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी नैतिकता को अपराध मानती है।

टीएमसी से निष्कासित विधायक संदीपान साहा ने आरोप लगाया कि पार्टी में नैतिक आचरण को भी पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाता है। उन्"होंने कहा "इस पार्टी में नैतिकता की बात करने वाले किसी भी व्यक्ति को पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त माना जाएगा, क्योंकि पार्टी खुद किसी भी नैतिक आचरण में शामिल नहीं होती।"

ॅल्लं३४१ फ्न्न्६ ओस्रील्ल२

उन्होंने आगे कहा, "अगर आज हमें नैतिकता बनाए रखने के लिए निलंबित किया गया है [पार्टी कहती है कि निष्कासित किया गया है], तो हम वास्तव में काफी खुश हैं।" जब उनसे पूछा गया कि क्या वह किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे, तो उन्होंने जवाब दिया:

"नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसके बारे में क्यों सोचूंगा?"

विवाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के वरिष्ठ नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के रूप में नामित करने वाले एक पत्र को लेकर है। जिसमें कथित जाली हस्ताक्षर का मामला है। साहा का आरोप है कि उन्होंने और अन्य विधायकों ने केवल उपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, किसी प्रस्ताव पर नहीं, और उन्हें यह नहीं पता था कि इसे समर्थन के रूप में माना जाएगा।

राज्य सीआईडी इस पत्र पर विधायकों के कथित जाली हस्ताक्षरों की जांच कर रही है और इस संबंध में कई पार्टी नेताओं को नोटिस दिए गए हैं। पार्टी उपाध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित एक संचार के अनुसार, साहा और उनके साथी विधायक ऋतब्रत बनर्जी, जो एंटाली और उलुबेरिया पुरबा सीटों से थे, को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्राथमिक सदस्यता से "तत्काल प्रभाव से" निष्कासित कर दिया गया।

पार्टी ने अपने निष्कासन के कारणों का खुलासा करते हुए कहा कि दोनों "पार्टी के अधिकृत नेतृत्व द्वारा बुलाई गई बैठकों में बार-बार शामिल होने में विफल रहे थे" और "पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे"। ये निष्कासन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुए।

मंत्री इरफान अंसारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना, कहा - मजाक का पात्र बन गए हैं मुख्यमंत्री योगी

(जीएनएस)।

दुमका : झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा निशाना साधा है. दुमका में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ आज मजाक के पात्र

बन गए हैं. इरफान अंसारी ने योगी को हिदायत देते हुए कहा कि - उड़ लीजिए जरा दिन, आपको शासन चलाने का लूर (ढंग) नहीं है.

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि बहुत मुश्किल से बाप-दादाओं के द्वारा आशियाना बनाया जाता है, लेकिन वे लगातार बुलडोजर से उसे ढाए जा रहे हैं. उन्हें गरीबों की हाय लगेगी. भाजपा अब उत्तरप्रदेश में सत्ता में आने वाली नहीं है. यह बातें इरफान अंसारी ने दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही. वे एक केस में पेशी के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट आए हुए थे.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पश्चिम बंगाल में तृणमूल नेताओं की पिटाई पर कहा कि यह सब भाजपा के द्वारा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी पर जिस तरह जानलेवा हमला हुआ, वह काफी गंभीर विषय है. पश्चिम बंगाल में सत्ता इनसे संभल नहीं रहा है. हमने ममता बनर्जी और उनके भतीजे को झारखंड बुलाया है और कहा है कि हम आपको सुरक्षा प्रदान देंगे और इलाज भी कराएंगे. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में हमारी सरकार है, क्या हम लोगों ने भाजपा के लोगों के साथ हिंसा की?

इरफान अंसारी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ अनर्गल बयान बाजी करते हैं. तीन दिनों के अंदर उन्होंने अगर हमसे माफी नहीं मांगी तो वह एफआईआर करेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य शिबू सोरेन, फुरकान अंसारी जैसे नेताओं ने संघर्ष कर अलग कराया. अगर झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ रहता तो बाबूलाल मरांडी बिहार विधानसभा के बाहर कटोरा लेकर बैठे नजर आते.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आज दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भी निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि यहां काफी कमी है जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने बताया कि यहां के अधीक्षक को बेहतर व्यवस्था नहीं होने पर हमने फटकार भी लगाई है और सब कुछ दुरुस्त करने का निर्देश दिया है.

सम्पादकीय

हिंसा और आरोप-प्रत्यारोप के चक्र में प. बंगाल

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर हिंसा और आरोप-प्रत्यारोप के चक्र में फंस गई है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनजा पर स्थानीय लोगों द्वारा अंडे, पत्थर और जूते फेंकने की घटना ने न केवल राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि अस्पतालों की निष्पक्षता और राजनीतिक सहिष्णुता पर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। यह घटना उस समय हुई जब अभिषेक बनजा हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के बाद कथित टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों के शिकार परिवारों से मिलने पहुंचे थे। खासतौर पर टीएमसी कार्यकर्ता संजू कर्मकार की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात का कार्यक्रम था। वीडियो फुटेज में देखा गया कि उनके काफिले पर भीड़ ने हमला बोल दिया, नारे लगाए गए "चोर-चोर" और सुरक्षा कर्मियों को उन्हें हेलमेट पहनाकर निकालना पड़ा। अभिषेक की शर्ट फटी हुई थी और वे भावुक नजर आए। अभिषेक बनजा ने इसे "पूर्व नियोजित हमला" करार दिया। उन्होंने दावा किया कि पत्थर उनकी आंख के पास से गुजरा और अगर हेलमेट न होता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। टीएमसी ने इसे बीजेपी समर्थकों द्वारा कराए गए हमले बताया और कहा कि नई सत्ता में विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है। दूसरी ओर, भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पाटा नेताओं ने कहा कि यह "जनता का गुस्सा" था, जो 15 साल के तृणमूल शासन के दौरान कथित भ्रष्टाचार, हिंसा और तानाशाही से त्रस्त है। भाजपा का तर्क है कि टीएमसी चुनाव हारने के बाद पोस्ट-पोल हिंसा फैला रही है और ध्यान भटकाने के लिए इस घटना को राजनीतिक रंग दे रही है। चुनावी परिवर्तन का संदर्भ इस घटना को समझने के लिए 2026 के विधानसभा चुनावों का परिप्रेक्ष्य जरूरी है। भाजपा ने भारी बहुमत हासिल किया - लगभग 207 सीटें, जबकि टीएमसी मात्र 80 सीटों पर सिमट गई। ममता बनजा सहित कई टीएमसी के मंत्री चुनाव हार गए। यह 15 साल के टीएमसी शासन का अंत था, जिसमें भ्रष्टाचार, सिंगुर-नंदीग्राम की यादें, संदेशखाली जैसे मामले और राजनीतिक हिंसा के आरोप लगते रहे। अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमलों के आरोप लग रहे हैं, जबकि टीएमसी पर पुराने मामलों का बदला लेने के आरोप। बंगाल में राजनीतिक हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण रूप से नई नहीं है। वामपंथी शासन, फिर टीएमसी और अब बीजेपी - हर बदलाव के साथ हिंसा के आरोप-प्रत्यारोप चले आए हैं। अस्पताल विवाद: नई बहस घटना के बाद अभिषेक बनजा को कोलकाता के बेल व्यू और अन्य अस्पतालों में ले जाया गया। यहीं से विवाद और गहरा गया। ममता बनजा ने आरोप लगाया कि अस्पतालों पर "ऊपर से दबाव" था। उन्होंने दावा किया कि कुछ अस्पताल उन्हें भर्ती करने से हिचकिचा रहे थे, डॉक्टरों को धमकियां मिल रही थीं और प्राथमिक उपचार में देरी की जा रही थी। ममता ने कहा कि यह केवल हमला नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ भी राजनीति है। हालांकि, अस्पतालों की रिपोर्ट्स अलग कहानी बयां करती हैं। डॉक्टरों ने चोटों को "सतही" बताया। छाती पर हल्की खरोंच के अलावा कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई। अभिषेक पूरी तरह होश में थे, बोल रहे थे और भता की जरूरत नहीं बताई गई। उन्हें बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया। टीएमसी ने इन रिपोर्ट्स पर सवाल उठाए और कहा कि दबाव के कारण सही जांच नहीं हो पाई। यह विवाद स्वास्थ्य संस्थाओं की स्वायत्तता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। यदि राजनीतिक दबाव का आरोप सही है, तो यह चिंताजनक है। लेकिन यदि यह अतिरंजित है, तो अस्पतालों और डॉक्टरों की गरिमा पर हमला है। राष्ट्रीय प्रतिक्रिया : राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने हमले की निंदा की और राजनीतिक हिंसा पर चिंता जताई। टीएमसी ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। बीजेपी का पलटवार था कि टीएमसी जब सत्ता में थी, तब विपक्षी कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और आम लोगों पर किस तरह अत्याचार हुए, उसकी जांच होनी चाहिए। हिंसा का चक्र तोड़ना होगा अभिषेक बनजा प्रकरण कई सवाल उठाता है: . राजनीतिक मतभेदों को हिंसा में बदलने की संस्वृति कब खत्म होगी? . सत्ता बदलने पर क्या हर बार बदले की भावना हावी हो जाएगी?

अनजाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को अजेय बनाने में मदद

(जीएनएस)।

इतिहासकार रामचंद्र गुहा का बेबाक विश्लेषण: कैसे गांधी परिवार की राजनीतिक गलतियों और दिशाहीनता ने अनजाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को अजेय बनाने में मदद की है।

कांग्रेस आज भी एक पारिवारिक कंपनी बनी हुई है, जिसका नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसके पास अनुशासन, गंभीरता और अनुभव की भारी कमी है।

साल 2024 के आम चुनावों के तुरंत बाद, मेरी मुलाकात कांग्रेस के एक युवा विधायक से हुई। उन्होंने मुझसे अपने नेता राहुल गांधी के लिए पांच सुझाव मांगे। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास सिर्फ एक ही सलाह है; और वह यह कि प्रियंका गांधी को वायनाड से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसके साथ ही मैंने यह भी जोड़ दिया था कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इस सलाह को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' ने उनकी साख बढ़ाने में काफी मदद की। इस यात्रा ने उन्हें आम जनता के एक जमीनी नेता के रूप में पेश किया। हालांकि, चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस ने खुद को फिर से एक पारिवारिक कंपनी के रूप में स्थापित कर लिया, जिससे उस यात्रा से मिले सभी फायदे बेकार हो गए।

प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट से जीत दर्ज की, जो उनके लिए उतनी ही सुरक्षित सीट है जितनी अमित शाह के लिए गांधीनगर। इसके बाद उन्होंने बड़े गर्व के साथ भाषण दिया कि कैसे वह और उनके भाई देश को एकजुट कर रहे हैं, जहां वह दक्षिण का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और उनके भाई उत्तर का।

इसके बाद, संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर होने वाली संसदीय बहस के लिए कांग्रेस ने प्रियंका को प्रमुख वक्ता के रूप में चुना। यह फैसला काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि यह उनकी अपनी ही दादी थीं जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर संविधान को कमजोर करने का काम किया था।

इस बीच, आम चुनावों में कांग्रेस को मिली 99 सीटों ने राहुल गांधी के इर्द-गिर्द मौजूद चापलूसों का उत्साह बढ़ा दिया। उन्होंने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि राहुल अब प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार हैं। दिल्ली के उन बुद्धिजीवियों और पत्रकारों ने भी इन दावों को हवा दी, जिनकी सत्ता-विरोधी छवि उनके गलत आकलन के कारण धुंधली पड़ गई थी और शायद वे राजनीतिक गुरु बनने के लालच में ऐसा कर रहे थे।

समय से पहले मिली खुशी

दो साल बाद, हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह खुशी कितनी जल्दबाजी में मनाई गई थी। केरल जैसी एकाध राज्य इकाई को छोड़ दें, जो व्यवस्थित है और कभी-कभार विधानसभा चुनाव जीत सकती है, तो देश के ज्यादातर हिस्सों में कांग्रेस ने लगातार अपना जनाधार खोया है।

भारतीय जनता पार्टी अब गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कई अन्य राज्यों में स्वाभाविक सत्ताधारी पार्टी बन गई है, जहां कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। राहुल गांधी पार्टी के इस पतन को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। 'द प्रिंट' की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, जब 2008 के आसपास राहुल ने कांग्रेस में औपचारिक नेतृत्व संभाला था, तब से लेकर अब तक देश भर में कांग्रेस विधायकों की संख्या लगभग आधी हो गई है। यह आंकड़ा 1,204 से गिरकर 676 पर आ गया है।

मैंने राहुल गांधी से मुलाकात की है और उनके साथ पत्राचार भी किया है और मैं जानता हूं कि वह एक अच्छे इंसान हैं। अगर यह थोड़ा-बहुत जान-पहचान न भी होती, तब भी मुझे उनके प्रति सहानुभूति होती। इसकी वजह उनके जीवन की व्यक्तिगत त्रासदियां हैं और यह सच्चाई भी है कि 55 साल की उम्र में भी वह अपनी मां की इच्छाओं के साधन मात्र बने हुए हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि उन्होंने सोनिया गांधी के निर्देश पर राजनीति में कदम रखा और आज भी उन्हीं के इशारे पर कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं।

हालांकि, जब बात गणराज्य के भविष्य की हो, तो इंसान को अपनी बात सीधे और बिना किसी लाग-लपेट के कहनी पड़ती है। राहुल गांधी भले ही कितने ही अच्छे इंसान हों, लेकिन जो लोग बीजेपी के नफरत भरे मौजूदा शासन को सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं, उन्हें अब राहुल गांधी को अपनी मुख्य उम्मीद के रूप में देखना बंद कर देना चाहिए।

नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी में अनुशासन, गंभीरता और एक ठोस राजनीतिक अनुभव का पूरी तरह अभाव है। जब वह भारत के चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण रवैये जैसा कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते भी हैं, तो उसे लगातार और मजबूती से आगे नहीं बढ़ाते। अक्सर देखने में आता है कि 'वोट चोरी' पर एकाध प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वह यूरोप या लैटिन अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते हैं।

सच तो यह है कि राजनीति में अपने 22 साल के करियर में, राहुल गांधी ने केवल 'भारत जोड़ो यात्रा' के कुछ महीनों के दौरान ही वह केंद्रित और कड़ी मेहनत दिखाई, जो बीजेपी के नेता हर समय करते हैं। आजकल, उनके राजनीतिक दखल ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' तक ही सीमित रहते हैं। इन पर तुरंत ढेरों लाइक्स तो मिल जाते हैं, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही लोग उन्हें भूल भी जाते हैं।

दिखावटी राजनीति

राहुल गांधी की गंभीरता की कमी उनके राजनीतिक दिखावे में भी साफ नजर आती है। उनकी यह भोली सोच है कि मछुआरों के साथ तालाब में कूदने या शेफ के साथ रसोई में जाने से उनकी पार्टी को वोट मिल जाएंगे। राजनीतिक अनुभव की यह कमी इस बात से भी झलकती है कि उन्होंने कभी कोई असली नौकरी नहीं की।

कोई नहीं जानता कि 2004 में सांसद बनने से पहले राहुल गांधी के पास क्या रोजगार था। जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) दस साल तक सत्ता में रही, तब भी उन्होंने कोई मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया था। ऐसे में भारतीय मतदाता उन पर इस विशाल और विविधतापूर्ण देश का एक प्रभावी प्रधानमंत्री बनने का भरोसा क्यों करें, वह भी तब जब दुनिया भर में भू-राजनीतिक चुनौतियां लगातार खतरनाक होती जा रही हैं?

अंततः, राहुल गांधी में अपनी पुरानी गलतियों से न सीख पाने की एक बड़ी कमी है। 2019 में 'चौकीदार चोर है' का अभियान उन पर बुरी तरह भारी पड़ा था। इसके बावजूद, वह शासन की विफलताओं या जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने के बजाय, व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री पर हमले करना (उन्हें कायर, समझौतावादी आदि कहना) जारी रखते हैं।

कांग्रेस के भीतर कई लोग इन आलोचनाओं को स्वीकार करते हैं। लेकिन गांधी परिवार के प्रति जीवन भर के समर्पण के कारण, उनका मानना है कि राहुल की जगह उनकी बहन को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाना चाहिए। उन्हें अब यह अहसास हो गया है कि राहुल नए नेहरू नहीं बन सकते, इसलिए वे उम्मीद कर रहे हैं कि प्रियंका नई इंदिरा साबित होंगी।

यह सच है कि हिंदी भाषा में भाषण देने के मामले में प्रियंका अपने भाई से कहीं बेहतर हैं और भारत की एक बड़ी आबादी इस भाषा को समझती है। हालांकि, वह भी वंशवाद के उस भारी बोझ तले दबी हैं। हो सकता है कि मतदाताओं को बूथ तक खींच लाने में वह अपने भाई से भी कम सफल रहें। जब 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में प्रियंका ने पहली बार कांग्रेस के चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया था, तब पार्टी का वोट शेयर केवल 2.27% रहा था।

वंशवाद का विशेषाधिकार

वैसे, हाल के विधानसभा चुनावों से एक ऐसा सबक भी मिला है जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। इन चुनावों के नतीजे वंशवाद के विशेषाधिकार के खिलाफ एक स्पष्ट नकारात्मक टिप्पणी थे। असम में तरुण गोगोई के बेटे के कांग्रेस प्रचार का नेतृत्व करने से बीजेपी को फायदा हुआ और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा अपने भतीजे अभिषेक को बढ़ावा देने से भी बीजेपी को लाभ मिला। तमिलनाडु में स्टालिन द्वारा अपने बेटे उदयनिधि को आगे बढ़ाने से विजय को मदद मिली और केरल में विजयन द्वारा अपने दामाद को बढ़ावा देने से कांग्रेस को फायदा हुआ। बेशक, इन चुनावी नतीजों के पीछे कई अन्य कारण भी थे, लेकिन यह निश्चित रूप से उनमें से एक बड़ा कारण था।

कांग्रेस के 'प्रथम परिवार' की इन आलोचनाओं का मतलब यह कतई नहीं है कि मैं मौजूदा शासन का समर्थन कर रहा हूं। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से लिखे गए अपने कई लेखों में, मैंने इस बात का दस्तावेजों के साथ जिक्र किया है कि कैसे इस सरकार ने सार्वजनिक संस्थानों को खोखला किया है। इसने प्रेस और न्यायपालिका को डराया है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर किया है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ क्रूरता की है, एक त्रुटिपूर्ण विदेश नीति अपनाई है, भारतीय विज्ञान को नुकसान पहुंचाया है, क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया है और हमारे जंगलों, मिट्टी, पानी तथा हवा को तबाह किया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि मई 2014 से भारतीय गणराज्य के इस पतन के मुख्य सूत्रधार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पार्टी बीजेपी हैं। लेकिन अब यह भी पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि मोदी और शाह को सत्ता हासिल करने और उसे मजबूत करने में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके इर्द-गिर्द मौजूद चापलूसों ने (जाने या अनजाने में) उनके मददगारों की भूमिका निभाई है।

मुझे अपनी बात निराशाजनक मोड़ पर खत्म नहीं करनी चाहिए। फिलहाल, मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अजेय नजर आती है। लेकिन हंगरी में विक्टर ओर्बन और फिडेस पार्टी भी ऐसी ही दिखती थी। फिर भी उन्हें एक बिल्कुल अज्ञात व्यक्ति पीटर मग्यार और उनकी नई टिसा पार्टी ने शानदार तरीके से सत्ता से बेदखल कर दिया।

चुनाव से दो साल पहले, मग्यार ने बिना थके पूरे देश की यात्रा की। वह छोटे शहरों और यहां तक कि गांवों में भी गए ताकि उस सत्तावादी नेता के खिलाफ अपना पक्ष रख सकें जिसने हंगरी को चलाया और बर्बाद कर दिया था। मग्यार ने वामपंथी, उदारवादी और मध्य-दक्षिणपंथी सहित सभी विपक्षी दलों का एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए जी-तोड़ मेहनत की। उनका एक नया चेहरा होना, भ्रष्टाचार या वंशवाद के दाग से मुक्त होना और उनकी कड़ी मेहनत, यह सब उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई।

जैसा कि एक हंगेरियन संपादक ने फाइनेंशियल टाइम्स में मग्यार के बारे में कहा था: ह्ववह बेहद जुनूनी हैं। दूसरों के पास साधन हैं, लेकिन उन्होंने मैदान में उतरकर सारी जमीनी मेहनत की।ह्व अफसोस की बात है कि राहुल या प्रियंका गांधी के बारे में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता।

यह पूरी तरह से संभव है कि मोदी की बीजेपी के चारों ओर जो अजेयता का आभामंडल अभी दिख रहा है, वह आने वाले वर्षों में टूट जाए। सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र बदहाली में है; नीट (ठएएळ) घोटाला इसका एक जीता-जागता उदाहरण है। केंद्र सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की कीमतें अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, जो रुपये की भारी गिरावट, पूंजी के पलायन और रोजगार पैदा करने में विफलता के रूप में सामने आ रही हैं।

2029 के आम चुनाव की तैयारियों के बीच, अधिक से अधिक हिंदुओं को यह अहसास हो सकता है कि मुसलमानों के प्रति नफरत किसी भी तरह से जीवन यापन की बढ़ती लागत, सम्मानजनक रोजगार की कमी या उनके बच्चों के अनिश्चित भविष्य के खतरे की भरपाई नहीं कर सकती।

वास्तव में, राजनीतिक व्यंग्य की बढ़ती लोकप्रियता, जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी (उखढ) के मीम्स की सफलता, यह दशार्ती है कि कई युवा भारतीयों ने सत्ताधारी पार्टी के झूठ और प्रोपेगेंडा की सच्चाई को समझना शुरू कर दिया है। बीजेपी यह बात जानती है, इसीलिए सीजेपी के अभिव्यक्ति के माध्यमों को बंद करने की हताश कोशिशें की जा रही हैं।

जब यह मोहभंग और गहरा होगा, तो इसे एक प्रभावी राजनीतिक चुनौती का रूप कौन देगा? कौन सा नेता, या नेताओं का समूह, मौजूदा सरकार की विफलताओं की परतें उधेड़कर और आर्थिक व सामाजिक सुधार के लिए एक रचनात्मक कार्यक्रम पेश करके देश भर के मतदाताओं को प्रेरित कर सकता है? उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए यह पूरी तरह से असंभव लगता है कि यह काम गांधी भाई-बहनों में से कोई एक या दोनों मिलकर कर सकते हैं।

यह लेख पहली बार 'द टेलीग्राफ' में प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र गुहा की

जी एंटरटेनमेंट ने खरीदे 2026 से 2034 तक के भारतीय प्रसारण अधिकार

(जीएनएस)।

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने एक बड़ा कदम उठाते हुए फीफा के 39 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल आयोजनों के मीडिया अधिकार हासिल कर लिए हैं, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े टूनामेंट जैसे फीफा विश्व कप 2026, फीफा महिला विश्व कप 2027 और फीफा विश्व कप 2030 शामिल हैं, और यह समझौता 2026 से लेकर 2034 तक लागू रहेगा, जिससे अगले लगभग 8 साल तक भारत में फीफा फुटबॉल का बड़ा प्रसारण मंच जी एंटरटेनमेंट बनने जा रहा है।

फुटबॉल के चाहने वालों के लिए आने वाला समय काफी खास होने वाला है, क्योंकि बड़े टूनार्मेंट अब भारत में और आसानी से देखे जा सकेंगे। इसी बीच जी एंटरटेनमेंट ने

फीफा के प्रसारण अधिकार हासिल कर लिए हैं। इस नए समझौते के तहत जी की फीफा कवरेज की शुरूआत 11 जून 2026 से होगी, जब फीफा विश्व कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शुरू होगा, और भारत में दर्शक यह सभी मैच जी के नए खेल चैनलों पर और ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकेंगे।

खेल प्रसारण में बड़ा निवेश

जी एंटरटेनमेंट का यह कदम भारत में फुटबॉल की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उठाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल आयोजनों की दर्शक संख्या बढ़ी है, डिजिटल माध्यमों पर दर्शकों की भागीदारी भी तेजी से बढ़ी है और यूरोपीय फुटबॉल लीगों के प्रति रुचि भी काफी बढ़ी है। कंपनी का मानना है कि वह ऐसे खेल अधिकारों में निवेश कर रही है जिनका भविष्य में बड़ा विस्तार और महत्व है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत गोयनका ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वे दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों को भारतीय दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोगों को जोड़ता है।

पीएम मोदी से मिले भजनलाल, बढ़ीं सियासी अटकलें

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक को राजस्थान की राजनीति और भाजपा संगठन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. हाल ही में राजस्थान भाजपा में संगठन महामंत्री की नियुक्ति हुई है, वहीं राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा भी जल्द होने की संभावना है. इसके अलावा लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर चचाएं जारी हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि बैठक में प्रदेश सरकार के कामकाज, संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई. राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि राजस्थान की तीन सीटों पर चुनाव होने हैं और भाजपा दो सीटों पर जीत की स्थिति में है. मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित पिचवाई चित्रकला भेंट की. बैठक के बाद भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत@2047 के विजन और राजस्थान के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की.

जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक को राजस्थान की राजनीति और भाजपा संगठन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब प्रदेश भाजपा में हाल ही में संगठन महामंत्री

की नियुक्ति हुई है, राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा निकट है और लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार व फेरबदल की चचाएं भी राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच प्रदेश सरकार के कामकाज की समीक्षा के साथ-साथ संगठनात्मक मजबूती, आगामी राजनीतिक रणनीति और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई होगी. पिछले तीन महीनों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रधानमंत्री मोदी से यह तीसरी मुलाकात है. ऐसे में इस बैठक को राजस्थान में आने वाले समय के राजनीतिक फैसलों से जोड़कर देखा जा रहा है.

मुख्यमंत्री की यह मुलाकात आगामी राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में भी अहम मानी जा रही है. राजस्थान में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होने हैं. विधानसभा में संख्या बल के आधार पर भाजपा दो सीटों पर जीत दर्ज करने की स्थिति में है. राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि एक सीट पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा मौका मिल सकता है. वहीं दूसरी सीट के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, अलका गुर्जर और उद्योगपति नरसी कुलहरी के नाम चर्चा में हैं. संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ फीडबैक साझा किया. माना जा रहा है कि अगले एक-दो दिनों में भाजपा राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है. यही वजह है कि इस मुलाकात को टिकट चयन की प्रक्रिया से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित एक सुंदर पिचवाई पेंटिंग भेंट की. पिचवाई राजस्थान की विश्वप्रसिद्ध पारंपरिक चित्रकला शैली है, जिसकी उत्पत्ति नाथद्वारा से मानी जाती है. यह कला मुख्य रूप से भगवान श्रीनाथजी और भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं, रास उत्सव, गोवर्धन पूजा और धार्मिक प्रसंगों को दशार्ने के लिए जानी जाती है.

कपड़े पर हाथ से बनाई जाने वाली इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों, सूक्ष्म ब्रश वर्क, बारीक रेखांकन और समृद्ध राजस्थानी सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. परंपरागत रूप से पिचवाई चित्र मंदिरों में श्रीनाथजी की प्रतिमा के पीछे सजाए जाते थे. आज यह कला राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है और देश-विदेश में इसकी विशेष मांग है. मुख्यमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री को भेंट की गई यह पेंटिंग राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कृष्ण भक्ति का प्रतीक मानी जा रही है.

मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा, महिला, किसान और अंत्योदय के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्पण तथा विकसित भारत@2047 के निर्माण के लिए उनका विजन और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणादायी है. उन्होंने कहा कि राजस्थान के प्रति प्रधानमंत्री का विशेष स्नेह, आत्मीय जुड़ाव और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता प्रेरणा का स्रोत है. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राजस्थान आधारभूत संरचना, निवेश, जल प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है.

उनका मार्गदर्शन और सहयोग विकसित राजस्थान के संकल्प को निरंतर शक्ति प्रदान कर रहा है. राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही इस मुलाकात के बाद अब राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा, संगठनात्मक बदलाव और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चचाएं और तेज हो गई हैं.

पाकिस्तान को मिल गई टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी, भारतीय टीम खेलने नहीं जाएगी, आईसीसी ने की घोषणा

(जीएनएस)।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने साल 2028 में होने वाले महिला टी20 विश्व कप के लिए अपने रोडमैप का ऐलान कर दिया है। इस बड़े टूनार्मेंट की मेजबानी का अधिकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को सौंपा गया है। घरेलू मैदान पर होने वाले इस इवेंट को लेकर पड़ोसी देश में काफी उत्साह है।

क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव भी सामने आया है। भारतीय महिला टीम के सभी मुकाबले पाकिस्तान से बाहर किसी न्यूट्रल (तटस्थ) वेन्यू पर आयोजित किए जाएंगे। आईसीसी ने यह कदम हाइब्रिड मॉडल की नीति के तहत उठाया है, ताकि बिना किसी बाधा के टूनामेंट पूरा हो सके।

यह पहला मौका नहीं है जब सुरक्षा और कूटनीतिक कारणों से ऐसा फैसला लिया गया हो। इससे पहले पुरुषों की चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी भारत-पाकिस्तान मैचों के लिए इसी तर्ज पर न्यूट्रल ग्राउंड फॉमूर्ला अपनाया गया था। वैश्विक संस्था ने इवेंट को प्रभावित होने से बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया है।

प्रतियोगिता के प्रारूप की बात करें तो 2028 के इस महाकुंभ में कुल 12 टीमें चमचमाती ट्रॉफी के लिए आपस में भिड़ेंगी। टूनार्मेंट में सीधे प्रवेश के लिए आईसीसी ने कड़े नियम बनाए हैं, जिसके तहत कुल 10 टीमों को सीधे ग्रुप स्टेज में जगह दी जाएगी।

इस सीधी एंट्री में पिछले टी20 विश्व कप की शीर्ष आठ टीमें शामिल होंगी। इसके साथ ही मेजबान होने के नाते पाकिस्तान को डायरेक्ट टिकट मिलेगा, जबकि बची हुई जगह रैंकिंग के आधार पर तय होगी। बाकी बची दो टीमों का फैसला एक ग्लोबल क्वालिफायर टूनार्मेंट के जरिए किया जाएगा।

यह तो साफ हो गया कि टीम इंडिया के मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर आयोजित किए जाएंगे लेकिन स्थान के बारे में खुलासा इवेंट के समय पता चलेगा। इसमें अभी काफी समय है। संभवतः टीम इंडिया का वेन्यू यूएई के किसी स्टेडियम में हो सकता है। भारत में महिला वनडे वर्ल्ड कप के दौरान भी पाकिस्तान के मुकाबले श्रीलंका में आयोजित हुए थे।

कौन हैं ये दो विधायक? जिन्हें ममता बनर्जी ने टीएमसी से किया निष्काषित

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा से मिली करारी हार के बाद से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के अंदर लगातार उठापटक जारी है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने दो विधायकों, संदीपान साहा और ऋतब्रत बनर्जी, को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया।

(पार्टी ने दोनों नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और संगठन के हितों के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप लगाया है। इस कार्रवाई को

पार्टी अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

टीएमसी विधायक संदीपन साहा उन करीब 60 विधायकों में शामिल थे जो ममता बनर्जी द्वारा कालीघाट स्थित आवास पर बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक में नहीं पहुंचे। बड़ी संख्या में विधायकों की अनुपस्थिति के कारण बैठक रद्द करनी पड़ी। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि अधिकांश विधायक अपने क्षेत्रों में हिंसा के विरोध से जुड़े कार्यक्रमों में व्यस्त थे और उन्होंने इसकी सूचना पहले ही दे दी थी

1 जून को जारी निष्कासन नोटिस में तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि दोनों विधायक पार्टी द्वारा नामित होने के बावजूद अधिकृत नेतृत्व की ओर से बुलाई गई बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे। पार्टी के अनुसार, यह व्यवहार संगठनात्मक अनुशासन के खिलाफ था और नेतृत्व के निदेर्शों की अवहेलना है।

PRGI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

10 स्वर्ण समेत 19 पदक: दिखा भारतीय युवाओं का दम; प्रधानमंत्री मोदी ने एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स टीम को दी बधाई

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, भारत ने 22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा एथलीटों को बधाई देते हुए कहा कि उनका प्रदर्शन देश की युवा प्रतिभा, दृढ़ता और उत्कृष्टता का प्रतीक है।

भारत ने 22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक अपने नाम किए। भारतीय दल ने 10 स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। मेजबान चीन 25 पदकों और 14 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि जापान 18 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन की देशभर में सराहना हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर भारतीय दल को बधाई दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा, '22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीतने के लिए भारतीय दल को बधाई। यह शानदार प्रदर्शन हमारे युवा एथलीटों के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को दशार्ता है।

मुझे उम्मीद है कि उनकी ये उपलब्धियां आने वाले वर्षों में और अधिक युवा भारतीयों को खेलों की ओर प्रेरित करेंगी।' प्रधानमंत्री के इस संदेश को भारतीय एथलेटिक्स के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

आखिरी दिन भारत ने जीते तीन स्वर्ण पदक

चैंपियनशिप के अंतिम दिन भारत ने तीन स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान का शानदार समापन किया। सबसे यादगार प्रदर्शन महिलाओं की 4७400 मीटर रिले टीम ने किया। नीरू पाठक, भूमिका संजय नेहते, तहूरा खातून और सेहनूर बावा की चौकड़ी ने 3:38.07 सेकेंड का समय निकालते हुए नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। यह प्रदर्शन प्रतियोगिता के सबसे बड़े आकर्षणों में शामिल रहा। महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में मुस्कान ने 16:53.08 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं, वेंकटराम रेड्डी मोगली ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में 1:48.27 सेकेंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय निकालकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

फील्ड इवेंट्स में निश्चय ने पुरुषों की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में 60.10 मीटर का थ्रो कर रजत पदक जीता। यह नया भारतीय अंडर-20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। इसके साथ ही वह इस वर्ग में 60 मीटर की दूरी पार करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए।

महिलाओं की 4७100 मीटर रिले टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। काजल हीराभाई वाजा, भावना जी, आरती और निपम ने 45.05 सेकेंड का समय निकालकर भारत को दूसरा स्थान दिलाया।

भविष्य के सितारों ने दिखाई ताकत

इस चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने न सिर्फ पदक जीते, बल्कि कई राष्ट्रीय और चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी बनाए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय एथलेटिक्स की नई पीढ़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री मोदी का संदेश भी इसी विश्वास को मजबूत करता है कि भारत के युवा खिलाड़ी आने वाले वर्षों में विश्व स्तर पर देश का नाम और ऊंचा करेंगे।

'नालायक औलादों को समझा लो, वरना...', सूर्या हत्याकांड पर सीएम योगी की चेतावनी- दोस्ती में चाकूबाजी बर्दाश्त नहीं

(जीएनएस)।

गाजियाबाद। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोमवार को उस समय कड़ा रुख दिखा, जब वे बिजनौर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने कड़े लहजे में कहा, 'चाकूबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।'

सोमवार को बिजनौर के एक कार्यक्रम में गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड को लेकर सीएम योगी ने कहा, 'हम सज्जन के लिए सज्जन हैं और दुर्जन के लिए दुर्जन।'

सीएम योगी ने कहा कि बकरीद

पर गाजियाबाद में हिंदू युवक की हत्या की गई लेकिन, इस पर विपक्ष चुप रहा। उन्होंने कहा, 'नालायक औलादों को समझा लो, नहीं तो उन्हें सबक सिखाना होगा।'

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा, 'गाय को पशु मानने वाले इंसान नहीं है, गाय स्वाभाविक हमारी माता हैं।'

सूर्या पर चाकू से किया था हमला

बता दें कि ईद के दिन गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या नाम के युवक को चाकू से हमला करके घायल कर दिया गया था। इसके बाद सूर्या की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

गाजियाबाद पुलिस ने सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

मऊ: 'प्राइवेट स्कूल कर रहे धन उगाही, सीएम योगी खोलें सरकारी कन्या कॉलेज', मुहम्मदाबाद गोहना में उठी बड़ी मांग

(जीएनएस)।

मऊ के मुहम्मदाबाद गोहना में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज न होने से गरीब बेटियों की पढ़ाई छूट रही है. प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस और धन उगाही से परेशान स्थानीय जनता, समाजसेवियों और नेताओं ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहां तुरंत सरकारी कन्या कॉलेज खोलने की मांग की है, ताकि छात्राओं को सुरक्षित माहौल में बेहतर और मुफ्त शिक्षा मिल सके.

उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत मुहम्मदाबाद गोहना तहसील में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज न होने के कारण बालिकाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. क्षेत्र में सरकारी विकल्प न होने से गरीब परिवारों की बेटियां या तो पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं या फिर निजी स्कूलों की महंगी फीस के जाल में फंसी हैं. इस गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और आम जनता ने सुर में सुर मिलाकर यहां तत्काल एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खोलने की मांग उठाई है, ताकि क्षेत्र की बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो सके.

बीजेपी नेता लाल जी वर्मा ने सीएम योगी को सौंपा ज्ञापन

लोकल 18 से विशेष बातचीत करते हुए पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष व भाजपा नेता लाल जी वर्मा ने बताया कि मुहम्मदाबाद गोहना में कोई राजकीय कन्या इंटर कॉलेज न होने से छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. राजकीय कॉलेज न होने के कारण गरीब तबके के लोग अपनी बेटियों को प्राइवेट विद्यालयों में नहीं पढ़ा पाते और वे शिक्षा से वंचित रह जाती हैं. यदि यहां राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खुल जाए, तो उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने में काफी आसानी होगी.

उन्होंने आगे बताया कि इस मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है. सरकार की वर्तमान नीति भी प्रत्येक ब्लॉक में कन्या इंटर कॉलेज खोलने की है. वह खुद अपने राजनीतिक जीवन में हर स्तर पर शासन-प्रशासन के सामने इस राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की मांग को प्रमुखता से उठाते चले आ रहे हैं.

बीजेपी में कौन बनेगा हिंदुत्व का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय? इन तीनों में रेस शुरू!

निजी स्कूलों की भारी फीस से गरीब छात्राएं पढ़ाई छोड़ने को मजबूर

भाजपा नेता लाल जी वर्मा ने जोर देकर कहा कि यदि यहां राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खुल जाता है, तो बेहद गरीब परिवार की बालिकाओं को भी सही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी. हालांकि, क्षेत्र में राजकीय डिग्री कॉलेज तो खोल दिया गया है, जिससे वहां उच्च शिक्षा ग्रहण करने में लोगों को सहूलियत हो रही है, लेकिन राजकीय इंटर कॉलेज (11वीं-12वीं) न होने से गरीब परिवारों की कन्याएं बीच में ही अशिक्षित रह जाती हैं. यदि यह कॉलेज खुल जाए तो यह बड़ी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी.

इसी क्रम में स्थानीय सभासद नंदलाल सोनकर ने बताया कि इस क्षेत्र में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज न होने से जमीनी स्तर पर काफी दिक्कतें आ रही हैं. गरीब परिवार की कन्याएं शिक्षा की मुख्यधारा से बहुत दूर होती जा रही हैं. प्राइवेट स्कूलों में अत्यधिक फीस होने की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राएं पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही हैं. इसलिए यहां अविलंब राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खोलना अति आवश्यक हो गया है.

सुरक्षा का संकट और निजी संस्थानों की धन उगाही से जनता त्रस्त

पूर्व बसपा प्रत्याशी डॉ. धर्म सिंह गौतम ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि मुहम्मदाबाद गोहना में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज न होने से तमाम तरह की व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं. अक्सर घर से दूर निजी और प्राइवेट संस्थानों में जाते समय छात्राएं रास्ते में किसी न किसी अप्रिय घटना या दुर्घटना की शिकार हो जाती हैं. ऐसे असुरक्षित माहौल में वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पातीं और सिर्फ एडमिशन लेकर ही स्कूल छोड़ देती हैं. यदि यहाँ सरकारी कन्या इंटर कॉलेज खुल जाए, तो वहां योग्य और चयनित शिक्षकों द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी, जिससे बेटियां शिक्षित बनेंगी और अपना भविष्य संवार सकेंगी. पूरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर घर की कन्या का शिक्षित होना बहुत जरूरी है.

वहीं, स्थानीय नागरिक जितेंद्र यादव ने निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बताया कि सरकारी कॉलेज न होने से छात्राओं को मजबूरी में निजी विद्यालयों में दाखिला लेना पड़ता है, जहां फीस के नाम पर तगड़ी वसूली की जाती है. गरीब परिवारों के पास इतना बजट नहीं होता कि वे इस महंगी पढ़ाई का खर्च उठा सकें, जिसके कारण उनकी बेटियां शिक्षा से महरूम रह जाती हैं. प्राइवेट विद्यालयों में फीस के नाम पर सिर्फ धन उगाही का खेल चल रहा है. यदि यहां राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खुल जाए, तो आम जनता को इस आर्थिक शोषण से बड़ी राहत मिलेगी और वे अपनी बेटियों को सुरक्षित माहौल में बेहतर शिक्षा दे पाएंगे.

गोंडा में अब दो किमी. से छोटी सड़क बनेगी सीसी, सीएम योगी की अपील के बाद नए तरीक से बन रहा एक्शन प्लान

(जीएनएस)।

गोंडा। तारकोल की किल्लत के चलते अब दो किलोमीटर से कम लंबाई की सभी सड़कें सीमेंट व कंक्रीट से बनाई जाएंगी। यही नहीं डामर बनाने में भी सीटीबी (सीमेंट टेस्ट बेस)व सीटीएसबी (सीमेंट टेस्ट सब बेस) तकनीक इस्तेमाल कर तारकोल की खपत घटाई जाएगी।

खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते तारकोल की किल्लत बरकरार है। मार्च में रहा 46 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन का भाव अब 83 हजार रुपये मीट्रिक टन पहुंच चुका है। महंगे मूल्य के बाद भी यह नही मिल पा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने डामर की जगह सीसी रोड बनाने का निर्देश लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को दिया था।

इस समय सड़कों का निर्माण की कार्ययोजना बनाई जा रही है,जिनका निर्माण बारिश के बाद होगा। प्रत्येक विधानसभा से करीब 100 सड़कों के

नवनिर्माण का प्रस्ताव मिला है। सातों विधानसभा क्षेत्रों से मिले 700 सड़कों के निर्माण में एक किलोमीटर से छोटी सड़क लोक निर्माण की जगह दूसरे विभाग बनाएंगे जबकि दो किलोमीटर से कम लंबाई वाली सभी सड़कों को डामर की जगह सीसी (सीमेंट-कंक्रीट) रोड बनाया जाएगा। इससे तारकोल की खपत घटेगी और जलभराव में सड़क के टूटने का डर भी नहीं रह जाएगा।

नई तकनीक से डामर बनाने में घटेगी तारकोल की खपत

यही नही डामर सड़क बनाने में भी अब नई तकनीक का प्रयोग होगा। सड़क बनाने में पत्थर डालने के पूर्व निचली परत में सीटीबी (सीमेंट टेस्ट बेस) या उसके ऊपर दूसरी परत में सीटीएसबी (सीमेंट टेस्ट सब बेस) बनाया जाएगा। इससे डामर की मोटाई कम हो जाएगी, जिससे तारकोल कम लगेगा।

लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता योगेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब दो किलोमीटर से छोटी सड़क सीमेंट व कंक्रीट से बनेगी। साथ ही डामर में भी तकनीक से तारकोल की खपत घटाई जाएगी।

केजीएमयू दवा घोटाले में यूरोलॉजी विभाग पर बड़ा एक्शन, कर्मचारियों के लखनऊ छोड़ने पर रोक

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में दवा वितरण से जुड़े कथित घोटाले की जांच तेज हो गई है.

(जीएनएस)।

लखनऊः किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में दवा वितरण से जुड़े कथित घोटाले की जांच तेज हो गई है. प्रशासन ने यूरोलॉजी विभाग में तैनात दवा वितरण कर्मचारियों को तत्काल हटाते हुए सभी कर्मचारियों के लखनऊ से बाहर जाने पर रोक लगा दी है. दोषी पाए जाने पर कर्मचारियों से रिकवरी के साथ सेवा समाप्ति की भी तैयारी है.

क्या थी शिकायतः KGMU प्रशासन को शिकायत मिली थी कि यूरोलॉजी विभाग के दवा काउंटर पर संविदा कर्मियों की मिलीभगत से दवाओं की अनियमित बिक्री और वितरण में गड़बड़ी की जा रही है. मामले की गंभीरता देखते हुए प्रशासन ने जांच समिति गठित की. जांच शुरू होते ही यूरोलॉजी विभाग के दवा वितरण से जुड़े संविदा कर्मियों को काउंटर से हटा दिया गया है.

रिकवरी की जाएगीः KGMU प्रवक्ता

डॉ. केके सिंह ने बताया कि जांच समिति आज शाम तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों से आर्थिक रिकवरी की जाएगी और उनकी सेवाएं भी समाप्त की जा सकती हैं.साथ ही, जांच पूरी होने तक किसी भी कर्मचारी को लखनऊ छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि सबूतों से छेड़छाड़ या फरारी की आशंका न रहे.

KGMU में यह पहला मामला नहीं है जब दवा और उपकरणों की खरीद-वितरण पर सवाल उठे हों. इससे पहले भी अस्पताल में 119 करोड़ रुपये की दवाएं बिना गुणवत्ता जांच के मरीजों को देने और ढढढ मॉडल पर मशीनों के संचालन में अनियमितता के आरोप सामने आ चुके हैं.यूरोलॉजी विभाग में ढढढ मॉडल पर करीब 20 साल से अल्ट्रासाउंड मशीनें चल रही हैं, जिसको लेकर भी प्रशासन की निगरानी कमजोर रहने के आरोप लगते रहे हैं.

हाल ही में यूरोलॉजी विभाग में अल्ट्रासाउंड के दौरान महिला मरीज से छेड़छाड़ के मामले में एजेंसी के जरिए तैनात डॉक्टर और ड्यूटी पर मौजूद वार्ड आया को भी नौकरी से हटाया गया था. इन लगातार घटनाओं के बाद KGMU प्रशासन अब सख्त रुख अपनाते हुए सिस्टम में पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहा है.

प्रशासन का कहना है कि मरीजों को मिलने वाली दवाओं और इलाज में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

लखनऊ में आईटी सिटी का बढ़ेगा दायरा:छूटी जमीनों को भी योजना में शामिल करेगा LDA; 2 लाख परिवार को मिलेगा घर

(जीएनएस)।

लखनऊ में प्रस्तावित आईटी सिटी योजना का दायरा अब और बढ़ेगा। करीब 3490 एकड़ में विकसित की जा रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अब उन जमीनों को भी शामिल किया जाएगा, जो पहले अधिग्रहण प्रक्रिया से बाहर रह गई थीं। इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अलग से भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

योजना क्षेत्र से सटी और पूर्व में विभिन्न कारणों से छूटी हुई जमीनों को चिह्नित किया जा रहा है। इनमें अंसल एपीआई की सुशांत गोल्फ सिटी परियोजना के लिए आरक्षित कुछ भूमि भी शामिल है। एलडीए का मानना है कि भविष्य में विकास कार्यों में किसी

तरह की बाधा न आए, इसलिए योजना की सीमा से सटे किसी भी गाटे को बाहर नहीं छोड़ा जाएगा।

इन गांवों से लगी जमीन भी शामिल की जाएगी

योजना विस्तार के तहत सोनई कंजेहरा, पहाड़नगर टिकरिया, परेहटा और सिकंदरपुर अमोलिया समेत कई गांवों की सीमा से लगी भूमि को शामिल करने की तैयारी है। संबंधित गांवों के गाटावार अभिलेख और नक्शे उपलब्ध होने के बाद अधिग्रहण प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।

एलडीए के अर्जन विभाग ने मुख्य नगर नियोजक समेत संबंधित अधिकारियों से गाटावार डीपीआर और भूमि विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। दस्तावेज मिलने के बाद छूटी हुई जमीनों के अधिग्रहण का अलग प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि आईटी सिटी को एकीकृत रूप से विकसित करने के लिए पूरी परिधि को योजना में शामिल करना जरूरी है।

विधि कोर्सों में थ्योरी और इंटरनल मिलाकर 40 प्रतिशत अंक वाले होंगे पास, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने लागू की नई व्यवस्था

(जीएनएस)।

लखनऊ। बार काउंसिल आफ इंडिया के मानकों के अनुरूप उत्तीर्ण होने के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत अब लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी को किसी भी विषय में पास होने के लिए मुख्य लिखित परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन दोनों में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा।

बल्कि थ्योरी और इंटरनल दोनों के अंकों को मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर भी विद्यार्थी को उस विषय में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, पूरे सेमेस्टर के सभी विषयों को मिलाकर विद्यार्थी के कुल प्राप्तांक 45 प्रतिशत या उससे अधिक होने अनिवार्य हैं।

कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी ने कहा कि थ्योरी और इंटरनल मिलाकर 40 प्रतिशत पर पास होने का नया नियम और 75:25 की नई प्रणाली विद्यार्थियों

को तनावमुक्त करेगी। प्रवक्ता प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव की ओर से जारी सूचना के अनुसार लवि ने एलएल.बी. (त्रिवर्षीय) और पांच वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रविधानों को लागू करने की आधिकारिक घोषणा की है।

तय हुआ कि दोनों कोर्सों के सभी विद्यार्थियों को विषम से सम सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। इससे सैकड़ों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी और सत्र भी पूरी तरह नियमित बना रहेगा।

मूल्यांकन पद्धति में बड़ा बदलाव

पूर्व में लागू लिखित परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था, जो पहले 90 और 10 के अनुपात में विभाजित थी, उसे संशोधित कर दिया गया है। अब मुख्य लिखित परीक्षा के लिए 75 प्रतिशत अंक और आंतरिक मूल्यांकन (असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और अटेंडेंस) के लिए 25 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। कुल 100 अंक के संयुक्त मूल्यांकन में से विद्यार्थियों को पास होने के लिए 40 अंक लाने होंगे।

संशोधित मार्कशीट और परीक्षा फार्म की सूचना : परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के अनुसार, प्रथम सेमेस्टर के विधि विभाग की संशोधित मार्कशीट इन नए नियमों के आधार पर शीघ्र ही जारी की जाएगी। मार्कशीट जारी होने के तुरंत बाद ही सभी पात्र छात्र-छात्राएं आगामी सम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भर सकेंगे।

पंजाब में कैसे बना अकाली दल का दबदबा? कांग्रेस को बाहर करने वाली पार्टी ने क्यों खोया जनाधार

(जीएनएस)।

भारतीय राजनीति के इतिहास में क्षेत्रीय दलों का उभार और पतन हमेशा से बेहद दिलचस्प रहा है। पंजाब की राजनीति की कहानी में अगर किसी एक क्षेत्रीय दल ने सबसे गहरी छाप छोड़ी है, तो वह है शिरोमणि अकाली दल। एक समय ऐसा था जब पंजाब की राजनीति कांग्रेस बनाम अकाली दल के इर्द-गिर्द घूमती थी।

दिसंबर 1920 में एक धार्मिक जनसभा से उपजे इस दल का सफर सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहा।आधी सदी से भी अधिक समय तक पंजाब ने दोतरफा चुनावी मुकाबला देखा एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और दूसरी तरफ अकाली दल (बाद में भाजपा के साथ गठजोड़)।

'किस्सा कुर्सी दा' के इस एपिसोड में कहानी सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल की, जिसने सिख राजनीति को दिशा दी, कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी, कई बार सत्ता पर कब्जा किया और फिर धीरे-धीरे अपना जनाधार खोती चली गई।

जम्मू-कश्मीर की 'नेशनल कॉन्फ्रेंस' (1939) और तमिलनाडु की 'द्रमुक' (1949) से भी पुरानी राजनीतिक विरासत समेटे शिरोमणि अकाली दल का गठन दिसंबर 1920 में हुआ था। मूल रूप से यह एक 'कैडर-आधारित' और वैचारिक आंदोलन था, जिसे सिख समुदाय के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करने का जनादेश मिला था। उस समय गुरुद्वारा सुधार आंदोलन अपने चरम पर था और अकाली दल इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरा।

अकाली दल ने खुद को हमेशा गुरुद्वारों और सिखों की सर्वोच्च संस्था का रक्षक माना। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने आजादी के बाद पंजाब का भूगोल, डेमोग्राफिक और सियासी भविष्य तय किया। लेकिन स्थापना के बाद से ही यह दल कई बार आंतरिक गुटबाजी का शिकार हुआ। लेकिन जब-जब पंथ पर संकट आया, ये गुट एकजुट भी हुए।

विभाजन से पहले औपनिवेशिक पंजाब में सिखों की आबादी महज 15% थी। इस कारण अकाली दल उस दौर में केवल 'प्रतिनिधित्व' की राजनीति करता था। लेकिन 1947 में विभाजन के बाद जब पंजाब की सीमाएं बदलीं, तो अकाली दल ने भारतीय संघ के भीतर ही एक सिख-बहुसंख्यक राज्य यानी 'पंजाबी सूबा' की मांग को लेकर एक बड़ा भाषाई और धार्मिक आंदोलन छेड़ दिया।

साल 1966 में जब पंजाब की सीमाएं दोबारा खींची गईं और हरियाणा व हिमाचल प्रदेश अलग हुए, तब पंजाब एक सिख-बहुसंख्यक राज्य बना। इसके बाद से ही राज्य की सियासत कांग्रेस और अकाली दल के इर्द-गिर्द सिमट गई।

बात 1966 की है जब पंजाब की राजनीति लगभग दो ध्रुवों में बंट गई। एक तरफ कांग्रेस थी और दूसरी तरफ अकाली दल। लेकिन समस्या यह थी कि कांग्रेस केवल हिंदू वोटों तक सीमित नहीं थी। पार्टी को बड़ी संख्या में सिख मतदाताओं का भी समर्थन मिलता था। कांग्रेस हर चुनाव में बड़ी संख्या में सिख उम्मीदवार उतारती थी और ग्रामीण तथा शहरी दोनों इलाकों में उसकी मजबूत पकड़ थी। यही वजह रही कि अकाली दल को कई बार मजबूत जनाधार होने के बावजूद पूर्ण बहुमत हासिल करने में कठिनाई होती थी।

चीन ने गला पकड़ा तो भारत-भारत चिल्लाने लगे मुनीर, दोहराई 'फितना-अल-हिंदुस्तान' की बकवास

(जीएनएस)।

इस्लामाबादः बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों के लगातार हमलों के बाद चीन ने उढएउ प्रोजेक्ट्स और अपने इंजीनियरों की सुरक्षा में फेल रहने पर पाकिस्तान की फंडिंग रोकने की सीधी धमकी दे दी है. चीन के इस अल्टीमेटम और आर्थिक नाकेबंदी के डर से घबराए पाकिस्तानी फौज के मुखिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए तुरंत भारत पर ठीकरा फोड़ दिया और 'फितना-अल-हिंदुस्तान' का पुराना राग अलापना शुरू कर दिया. बलूचिस्तान फेलियर का इल्जाम

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में जब कोई देश अंदर से पूरी तरह खोखला हो जाता है तो वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाने लगता है. बलोच लड़ाकों के हाथों लगातार पिट रही पाकिस्तानी सेना के साथ भी इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है. बलूचिस्तान से गुजरने वाले उढएउ पर लगातार होते हमलों से परेशान चीन ने जब इस्लामाबाद का गला दबाया और फंडिंग रोकने की सीधी धमकी दी तो पाकिस्तानी फौज के मुखिया आसिम मुनीर के हाथ-पांव फूल गए. घबराहट और बेइज्जती को छिपाने के लिए मुनीर तुरंत बॉर्डर पर भागे और बिना किसी सबूत के भारत पर ठीकरा फोड़ते हुए 'फितना-अल-हिंदुस्तान' का पुराना राग अलापने लगे.

बलूचिस्तान पर लाचार मुनीर

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (इछअ) ने सुरक्षाबलों को ले जा रही जफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर एक बेहद सटीक और बड़ा धमाका

किया था? इस धमाके ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की सुरक्षा व्यवस्था के दावों को पूरी तरह मटियामेट कर दिया. अपनी नाक कटते देख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तुरंत ईद-उल-अजहा के मौके पर बलूचिस्तान के झोब और क्वेटा इलाकों में फ्रंटलाइन जवानों से मिलने पहुंचे. वहां मुनीर ने अपनी फौज और एजेंसियों की कमियों को सुधारने या बलोच विद्रोहियों से निपटने की कोई ठोस रणनीति बनाने की जगह, सीधे इसे एक विदेशी साजिश करार दे दिया.

नाकामी छिपाने के लिए नया नाम 'फितना-अल-हिंदुस्तान'

पाकिस्तानी सेना ने तो अब अपनी हर नाकामी पर पर्दा डालने के लिए एक नया शब्द 'फितना-अल-हिंदुस्तान' भी गढ़ लिया है. जब भी देश के भीतर कानून-व्यवस्था चरमराती है, रावलपिंडी के आला अफसर इस नए जुमले का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं. खुफिया एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ये पाकिस्तानी सेना की दशकों पुरानी और घिसी-पिटी रणनीति है. जब भी वे घरेलू मोर्चे पर अपने ही लोगों को सुरक्षा देने में फेल होते हैं, तो जनता का गुस्सा शांत करने के लिए भारत का नाम जपने लगते हैं. इस बार भी मुनीर ने यही किया ताकि पाकिस्तानी आवाम फौज से उसकी नाकामी पर सवाल न पूछ सके.

बीजिंग ने इस बार इस्लामाबाद को बहुत अल्टीमेटम दिया है. चीन इस बात से बेहद भड़का हुआ है कि अरबों डॉलर के चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (उढएउ) के प्रोजेक्ट्स और वहां काम कर रहे चीनी इंजीनियरों की सुरक्षा करने में मुनीर आर्मी पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई है.

चीन के गुस्से की वजह ये है कि उसके लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ग्वादर इलाके में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पूरी तरह ठप हो गए हैं. अब बीजिंग ने साफ धमकी दे दी है कि अगर उसके लोगों को मुस्तैद सुरक्षा नहीं मिली तो वो भविष्य में मिलने वाला सारा फंड पूरी तरह रोक देगा. कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए ये किसी मौत के फरमान जैसा है.

पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की डरी हुई सेना

हालत तो देखिए आसिम मुनीर ने संविधान में बड़े बदलाव करवाकर खुद को फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज घोषित कर दिया है. उन्होंने देश की पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली है और एक अघोषित तानाशाह बन चुके हैं लेकिन सेना की जमीनी हकीकत इस श्क्ह ठाठ-बाठ के बिल्कुल उलट है.

खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, बॉर्डर पर तैनात पाकिस्तानी फौजियों का हौसला इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. फ्रंट मोर्चों पर तैनात जवान खुद को बलूचिस्तान के पहाड़ों में बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं. बलूचिस्तान अब मुनीर आर्मी के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर निकल चुका है और भारत पर उंगली उठाना मुनीर की लाचारी को दिखाता है.

भारत पर दो-चार नहीं, 500 मिसाइलें दागे ईरान, यूपी के मुबारक खान ने पीएम मोदी को लेकर किया पोस्ट, मची खलबली

(जीएनएस)।

लखीमपुर। मैलानी कस्बा निवासी एक मुस्लिम युवक का इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें युवक पीएम मोदी पर मुसलमानों पर जुल्म करने का आरोप लगा रहा है। प्रधानमंत्री के जुल्मों से निजात पाने के लिए वह ईरान वालों से भारत पर दो चार नहीं, बल्कि 500 मिसाइलें दागने की मांग कर रहा है।

वायरल वीडियो से हिंदू संगठनों एवं भाजपाईयों में आक्रोश पनप गया। भाजपा कार्यकर्ता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि वीडियो वायरल करने के बाद मुबारक खान पंजाब भाग गया है।

नगर पंचायत मैलानी के वार्ड नंबर पांच निवासी मुबारक खान ने इंटरनेट मीडिया पर शनिवार को वीडियो वायरल कर पीएम मोदी को मुस्लिमों पर जुल्म करने वाला बताया है।

पीएम मोदी से छुटकारा दिलाने के लिए उसने ईरान वालों से भारत पर 500 मिसाइलें दागने की अपील की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही हिंदू संगठनों व भाजपाईयों में आक्रोश पनप गया।

शनिवार रात में ही अमर शहीद भगत सिंह सेवा समिति एवं भाजपा कार्यकर्ता मैलानी नगर पंचायत अध्यक्ष पति भवानी शंकर महेश्वरी के नेतृत्व में मैलानी थाना पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की मांग की।

कार्यकताओं ने कहा कि इस तरह का बयान देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हैं। भाजपा कार्यकर्ता निखिल प्रताप सिंह की तहरीर पुलिस ने मुबारक खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए घर से लेकर संभावित ठिकानों पर दबिश दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुबारक खान वीडियो वायरल होने के बाद से फरार है।

वहीं, घरवालों के मुताबिक मुबारक खान इस समय पंजाब में जल्द ही आकर पुलिस के सामने अपनी बात रखेगा। प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार मौर्य ने बताया कि आरोपित को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई हैं। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

'गाय हमारी माता है, पशु नहीं', राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे मौलानाओं पर बरसे सीएम योगी

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर बयान देने वाले मौलवियों और मौलानाओं पर तीखा निशाना साधा. उन्होंने कहा कि गाय हिंदू समाज के लिए सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि माता है और माता तथा पुत्र के बीच के रिश्ते को किसी सरकारी घोषणा की आवश्यकता नहीं होती. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ मौलाना लगातार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि गाय हमारे लिए पशु नहीं है. गाय हमारी माता है. साथ ही उन्होंने कहा कि माता और बेटे के बीच के रिश्ते को कभी घोषित नहीं किया जाता. यह संबंध आस्था, संस्कार और श्रद्धा से जुड़ा होता है.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग गाय को केवल पशु के रूप में देखते हैं, उनकी सोच पर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने कहा कि गाय को पशु कहने वाले लोग अपनी मानसिकता पर विचार करें. उनके अनुसार हिंदू समाज में गाय का स्थान हमेशा पूजनीय रहा है और उसे माता का दर्जा प्राप्त है. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में गौहत्या का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गौहत्या को लेकर सख्त कानून लागू हैं और जो लोग इसमें शामिल होते हैं, उन्हें उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग गाय की हत्या करते हैं या उसका समर्थन करते हैं, उन्हें अपने अनुयायियों को भी समझाना चाहिए कि ऐसे कार्यों का क्या अंजाम हो सकता है.

उन्होंने कहा कि गंगा और गाय दोनों भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. योगी ने कहा कि हिंदू समाज में किसी भी शुभ कार्य की शुरूआत गंगा पूजन और ईश्वर स्मरण के साथ की जाती है. इसलिए किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि गंगा और गाय का स्थान क्या है. मुख्यमंत्री ने बिजनौर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि यह महाभारत की धरती है और

महाभारत हमें यह शिक्षा देती है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है. उन्होंने कहा कि समाज को अपने सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए.

बिजनौर में मौलानाओं पर योगी का बड़ा हमला

कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए परिवारों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान हजारों लोगों की हत्या हुई थी और बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे. उन्होंने बताया कि ऐसे विस्थापित परिवारों की अब चार पीढ़ियां बीत चुकी हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय तक उनके अधिकार नहीं मिले. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अब इन लोगों को अधिकार पत्र उपलब्ध करा रही है और 1645 लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों ने इन विस्थापित परिवारों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने इन लोगों को उनके अधिकार देने की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए. अब उनकी सरकार इस दिशा में काम कर रही है और पात्र लोगों को अधिकार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है. योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संपत्तियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जा किया, यदि वे इन विस्थापित परिवारों के लिए कुछ करते तो समाज उनके बारे में अलग सोच सकता था. उन्होंने कहा कि इन परिवारों की चिंता उनकी सरकार ने की है और उन्हें अधिकार दिलाने का काम भी सरकार द्वारा किया जा रहा है.

गौ माता को पशु बताना कुबुद्धि

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई, लेकिन इस पर कई मौलाना और धार्मिक नेता चुप रहे. उन्होंने कहा कि वहां हिंदुओं की आबादी लगातार कम होती गई, लेकिन इसके खिलाफ कहीं से भी प्रभावी आवाज नहीं उठाई गई. उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का उल्लेख करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले शिवरात्रि, कांवड़ यात्रा, कृष्ण जन्माष्टमी और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान तनाव और विवाद की खबरें सामने आती थीं, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और त्योहार शांति के साथ संपन्न हो रहे हैं.

गाजियाबाद की एक घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दोस्ती की आड़ में होने वाली धोखाधड़ी या छल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनाएं सामान्य और कानून का पालन करने वाले लोगों के साथ हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास के नारे का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अहिंसा मानवता का आभूषण है, लेकिन जब समाज और राष्ट्र के सामने चुनौतियां खड़ी हों तो सजग और मजबूत रहने की आवश्यकता भी होती है. उन्होंने कहा कि जो लोग देश का विरोध करते हैं या बहन-बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ समाज को एकजुट होकर खड़ा होना होगा.

गाय को पशु कहने वालों की सोच पशुवत

अपने भाषण के अंत में मुख्यमंत्री ने फिर से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ज्ञापन देने की बजाय उन लोगों को अपने अनुयायियों को समझाना चाहिए जो बकरीद के अवसर पर गाय की तस्वीर लगाकर संदेश प्रसारित करते हैं. उन्होंने कहा कि समाज में सौहार्द और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार होना चाहिए तथा कानून का सम्मान सभी को करना चाहिए. मुख्यमंत्री का यह बयान अब राजनीतिक और सामाजिक चचाओं का विषय बन गया है. उनके संबोधन में गाय, गंगा, विस्थापित परिवारों, कानून व्यवस्था, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति और सामाजिक मुद्दों सहित कई विषय प्रमुख रूप से शामिल रहे.

जनता की निगाह पर चढ़े बालेन शाह? नेपाल में विरोध शुरू, क्या है वजह?

(जीएनएस)।

भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है। इसकी वजह बने हैं नेपाल के युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह। 31 मई को संसद में दिए गए उनके एक बयान ने नेपाल की राजनीति से लेकर भारत-नेपाल संबंधों तक कई सवाल खड़े कर दिए।

दिलचस्प बात यह है कि बालेन शाह को पहले संसद में कम बोलने के लिए आलोचना झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब जब उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, तो उनके बयान पर अपने ही देश में विवाद खड़ा हो गया।

संसद में पहली बार बोले बालेन शाह

31 मई को प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बालेन शाह ने नेपाल की संसद को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने माना कि भारत और नेपाल के बीच कई सीमा विवाद अभी भी अनसुलझे हैं। उन्होंने खास तौर पर कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख जैसे विवादित इलाकों का जिक्र किया, जो कई सालों से दोनों देशों के बीच तनाव की वजह बने हुए हैं।

भारत ही नहीं, नेपाल भी कर रहा है कब्जा?

अपने भाषण के दौरान बालेन शाह ने एक ऐसा दावा किया जिसने विवाद को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें पता चला कि सिर्फ भारत ही नेपाल की जमीन पर दावा नहीं करता, बल्कि नेपाल भी कुछ जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा किए हुए है। शाह ने संसद में कहा-

"प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि केवल भारत ने ही नेपाल की भूमि का अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारत की भूमि का अतिक्रमण किया है।"

उनका यह बयान नेपाल की पारंपरिक सरकारी लाइन से अलग माना जा रहा है।

ब्रिटेन और चीन को भी बातचीत में शामिल करने का सुझाव

बालेन शाह यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इस विवाद को सुलझाने के लिए केवल भारत और नेपाल ही नहीं, बल्कि चीन और यूनाइटेड किंगडम को भी बातचीत का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि यह विवाद उस दौर से जुड़ा हुआ है जब भारत पर ब्रिटिश शासन था। इसलिए ब्रिटेन की भी इस मामले में ऐतिहासिक जिम्मेदारी बनती है।

शाह ने कहा,

"हमने भारत और चीन के साथ-

साथ ब्रिटिश सरकार से भी बात की है। हमारा मानना है कि इंग्लैंड को भी इसमें रुचि लेनी चाहिए क्योंकि यह मुद्दा अंग्रेजी शासन के समय से जुड़ा हुआ है।"

आखिर क्या है कालापानी-लिपुलेख विवाद?

बालेन शाह की यह टिप्पणी उस समय आई जब संसद में कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र पर चर्चा चल रही थी। यह इलाका भारत, नेपाल और तिब्बत के त्रि-जंक्शन के पास स्थित है और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत का कहना है कि यह पूरा क्षेत्र उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है। वहीं नेपाल दावा करता है कि लिपुलेख और आसपास के इलाके उसकी सीमा में आते हैं। नेपाल अपने दावे के समर्थन में 1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि का हवाला देता है।

बयान के बाद नेपाल में शुरू हुआ राजनीतिक तूफान

बालेन शाह के बयान के तुरंत बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सांसदों ने मांग की कि प्रधानमंत्री की टिप्पणियों को संसद की कार्यवाही से हटाया जाए क्योंकि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए थीं। कई नेताओं ने इसे गैर-जिम्मेदाराना बयान करार दिया।

नेपाली कांग्रेस ने उठाए सवाल

नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष बिश्वा प्रकाश शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री की आलोचना की। उन्होंने लिखा-

"एक देश के प्रधानमंत्री को बोलने से पहले दस बार सोचना चाहिए। खासकर जब मामला संवेदनशील कूटनीतिक मुद्दों से जुड़ा हो। आखिर देश को प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत राय पर भरोसा करना चाहिए या सरकार की आधिकारिक नीति पर। क्या नेपाल वास्तव में किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा किए हुए है या फिर खुद अतिक्रमण का शिकार है।"

पूर्व विदेश मंत्री कमल थापा भी नाराज

नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री कमल थापा ने भी बालेन शाह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीमा विवादों को स्वीकार करना अलग बात है, लेकिन नेपाल ने कभी भी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है। थापा ने कहा-

"नेपाल हमेशा अपने पड़ोसियों की सीमाओं का सम्मान करने के सिद्धांत पर कायम रहा है।"

उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो उसे सार्वजनिक किया जाए और बताया जाए कि नेपाल ने आखिर भारत की कौन-सी जमीन पर कब्जा किया हुआ है।

पूर्व राजदूत ने भी किया दावा खारिज

भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य ने भी प्रधानमंत्री के दावे को गलत बताया। उन्होंने नेपाली मीडिया से कहा-

"नेपाली राज्य ने कहीं भी भारतीय भूमि का अतिक्रमण नहीं किया है। प्रधानमंत्री का यह दावा सही नहीं है।"

विदेश मंत्रालय को देना पड़ा स्पष्टीकरण

बढ़ते विवाद के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री का बयान सीधे तौर पर किसी सरकारी कब्जे की बात नहीं कर रहा था। असल में उनका संदर्भ उन सीमावर्ती इलाकों से था जहां कभी-कभी दोनों देशों के नागरिक नो-मैन्स-लैंड या सीमा के आसपास की जमीन का इस्तेमाल करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि कुछ ऐसे इलाके हो सकते हैं जहां भारतीय नागरिक नेपाली जमीन का उपयोग कर रहे हों या नेपाली नागरिक भारतीय जमीन का इस्तेमाल कर रहे हों।

भारत ने अभी तक नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

बालेन शाह के ताजा बयान पर भारत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि इसी महीने नेपाल ने लिपुलेख दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने पर आपत्ति जताई थी। उस समय भारत ने नेपाल के दावों को एकतरफा और आर्टिफीशियल विस्तार बताते हुए खारिज कर दिया था।

आखिर क्या है पूरा सीमा विवाद?

भारत और नेपाल के बीच कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को लेकर दशकों पुराना विवाद है।इस विवाद की जड़ 1816 की सुगौली संधि में है। संधि के अनुसार काली नदी दोनों देशों के बीच पश्चिमी सीमा तय करती है। लेकिन समस्या यह है कि संधि में कभी साफ नहीं बताया गया कि काली नदी का वास्तविक उद्गम स्थल कहां है।

1962 के युद्ध के बाद बढ़ा महत्व

1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से कालापानी क्षेत्र का रणनीतिक महत्व और बढ़ गया। तब से भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (क्ळइढ) यहां तैनात है और भारत इस इलाके को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानता है।

2020 में नया नक्शा, 2025 में नया नोट

साल 2020 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था जिसमें कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। बाद में नेपाल ने संविधान में संशोधन कर इस नक्शे को संवैधानिक मान्यता भी दे दी। इसके बाद 2025 में नेपाल ने 100 रुपये का नया नोट जारी किया जिस पर यही विवादित नक्शा छापा गया था।

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी हुआ विवाद

2026 में भी यह मुद्दा तब चर्चा में आया जब नेपाल ने लिपुलेख दर्रे के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने पर आपत्ति जताई। भारत और चीन के बीच इस रास्ते से व्यापार दोबारा शुरू करने की चर्चा पर भी नेपाल ने नाराजगी जताई थी। नेपाल का कहना है कि विवादित क्षेत्रों से जुड़े फैसले उसकी भागीदारी के बिना नहीं लिए जाने चाहिए।

आगे क्या होगा?

फिलहाल बालेन शाह के बयान ने नेपाल की राजनीति और भारत-नेपाल संबंधों में नई बहस छेड़ दी है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह नेपाल की पारंपरिक विदेश नीति से अलग एक नया संकेत हो सकता है। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह केवल प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत राय है या भविष्य में नेपाल सरकार की आधिकारिक नीति का हिस्सा बनेगा।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में काठमांडू और नई दिल्ली इस मुद्दे को किस तरह संभालते हैं और क्या सीमा विवाद को लेकर कोई नई कूटनीतिक पहल देखने को मिलती है।

विकासनगर में युवती से अश्लील हरकत करने वाला ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार, कृष्णानगर में भी सात लुटेरे अरेस्ट

(जीएनएस)।

लखनऊः राजधानी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने रविवार को दो बड़ी कार्रवाई की हैं। विकासनगर में युवती से अश्लील हरकत और जानलेवा हमला करने वाले ऑटो चालक को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पैर में गोली लगने पर दबोच लिया। वहीं, कृष्णानगर पुलिस और सर्विलांस सेल की टीम ने रविवार तड़के मुठभेड़ के बाद दिल्ली-एनसीआर से आकर लखनऊ में वारदात करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के दो बद¨ माशों को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर गिरोह के सरगना समेत पांच अन्य सदस्यों को भी दबोचा गया है।

युवती पर किया था जानलेवा हमला

विकासनगर इलाके में युवती से छेड़छाड़, अश्लील हरकत, गाली-गलौज और जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित ऑटो चालक सनी यादव पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 30 मई 2026 को एक पीड़ित पिता ने विकासनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री के साथ ऑटो चालक सनी यादव ने अश्लील हरकत की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। विरोध करने पर

आरोपी ने युवती पर जानलेवा हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

टेढ़ी पुलिया के पास घेराबंदी

रविवार को पुलिस को सूचना मिली कि वांछित आरोपित सनी यादव टेढ़ी पुलिया स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (ऋक) उत्तरी क्षेत्र के आवासीय परिसर के पास मौजूद है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने जब उसे घेरा, तो आरोपित ने तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली विकासनगर थाना प्रभारी आलोक कुमार सिंह के सरकारी वाहन के गेट पर जा लगी। इसके बाद आरोपित ने एक और फायर किया। पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में सनी यादव के दाहिने पैर में गोली लगी और वह गिर गया।

अवैध असलहा बरामद

मूल रूप से हुसैनगंज के रहने वाले सनी यादव को मौके से गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, दो खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है।

पैर में गोली लगने के बाद दो लुटेरे अरेस्ट

वहीं, दूसरे मामले में कृष्णानगर पुलिस और सर्विलास सेल की टीम ने रविवार तड़के मुठभेड़ के दौरान बाइक सवार दो लुटेरों को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। इसके बाद गिरोह का बड़ा नेटवर्क खोलते हुए पाच अन्य शातिरों को भी दबोच लिया गया।

मानस नगर रोड पर भिड़ंत

डीसीपी (साउथ) अमित कुमार आनंद ने बताया कि कृष्णानगर इलाके में बीते दिनों बाइक सवार बदमाशों ने एक सेल्समैन से लूट और एक विवाहिता से टप्पेबाजी की वारदात की थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने रविवार तड़के मानस नगर आशा राम बापू रोड पर चेकिंग अभियान चलाया था।